



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 मार्च, 2005/3 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

तारीख, शिमला, 23 मार्च, 2005

संख्या एच० पी० ई० आर० सी०/609.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42 की उप-धारा (5) के साथ पठित, धारा 181 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अक्टूबर, 2003 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग [उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच (फोरम) की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका], विनियम, 2003 में संशोधन करने हेतु बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसात पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बाबत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जाएगा।

इन निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योथल कमर्शियल कम्प्लैक्स, खलिनी, शिमला-171002 को सम्बोधित किये जाने चाहिए :-

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग [उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच (फोरम) की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका] (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2005 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग [उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच (फोरम) की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका] विनियम, 2003 के विनियम 3 के उप-विनियम (4) के खण्ड (ख) में आए शब्द “या रह चुका हो” के पश्चात् तथा चिन्ह और शब्द “;और” से पहले शब्द “या ऐसा व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रह चुका हो और इन्जीनियरी, वित्त, वाणिज्य, अर्थ शास्त्र, विधि या प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याओं का निपटान करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखता हो” अन्तःस्थापित किए जाएं।

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

सचिव।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT)

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Dated, Shimla, the 23rd March, 2005

No. HPERC/609.—The following draft regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, published in Rajpatra, Himachal Pradesh, Extra-ordinary dated 24th October, 2003, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by section 181, read with sub-section (5) of section 42, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and other powers enabling it in this behalf are hereby published as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration, after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with the objections or suggestions which may be received in respect thereto within the aforesaid period.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

Draft Regulations

1. Short title and Commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Second Amendment) Regulations, 2005.

(2) These Regulations will come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of regulation 3.—In case clause (b) of sub-regulation (4) of regulation

3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 after the words "a District Judge" but before the sign and word "; and" the words "or a person who is or has been the member of the Indian Administrative Service with minimum 20 years of experience in dealing with the problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law or management" shall be inserted.

By order of the Commission

Sd/-
Secretary.